

# राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

वर्ष 11 अंक 2

जुलाई-दिसम्बर 2009

1. "प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी – आविर्भाव से तिरोभाव तक" – डॉ. वंशीधर त्रिपाठी, सेवा निवृत्त प्रोफेसर समाजशास्त्र काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

भारत के महान अंतरविज्ञानी समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी, जिनके नाम पर प्रस्तुत शोध पत्रिका का नामकरण किया गया था, पर अब तक इस शोध पत्रिका में, चाहते हुए भी, हम कोई लेख नहीं दे सके थे। पत्रिका परिवार प्रख्यात समाजशास्त्री श्रद्धेय प्रोफेसर बंशीधर त्रिपाठी जी का आभारी है जिन्होंने 'प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी: आविर्भाव से तिरोभाव तक' नाम से प्रोफेसर मुकर्जी के जीवन पर प्रस्तुत लेख प्रदान करने की कृपा की है।

2. "विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एवं भूमण्डलीकरण का संकट" – प्रोफेसर के.पी. सिंह, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

भूमण्डलीकरण केवल अर्थव्यवस्था का विस्तार मात्र ही नहीं है अपितु इसके साथ उदारीकरण, आधुनिकीकरण, स्थानीयकरण, उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। यह व्यापार, प्रौद्योगिकी, उद्योग, अर्थव्यवस्था और आधुनिकता से जुड़ी संस्थाओं को सार्वभौमिक दिशा की ओर रूपान्तरित करती है। प्रस्तुत लेख में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव को उजागर किया गया है।

3. "मानसिक विकलांग बच्चों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास : चुनौतियाँ एवं सम्भावनायें" – अनिल कुमार सक्सेना, शोध अध्येता समाजकार्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), एस.व्ही. एस. चौहान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन एवं समाजकार्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

'सभी के लिए शिक्षा' – सरकार के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव होगी जब हम अपने एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस विशाल देश में पाठशाला जाने योग्य आयु के लगभग 21.5 करोड़ बच्चों में से 2.7 करोड़ विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा में ला पायेंगे। विकलांगता से ग्रसित इन बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की पृथक समस्याएं एवं चुनौतियां हैं। प्रस्तुत लेख इन्हीं चुनौतियों एवं संभावनाओं के विश्लेषण का एक प्रयास है।

4. "पंचायत सदस्यों में महिलाओं की स्थिति : उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी का एक अध्ययन" – प्रोफेसर अंजलि बहुगुणा, प्रोफेसर अर्थाशास्त्र विभाग, हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड), डा. पूनम धस्माना, अंशकालिक प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, बी.गोपाल रेड्डी, पौड़ी कैम्पस, हे.न.ब. केन्द्रीय वि.वि., श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा उनके लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गये तथा मार्च 2008 में कुछ राज्यों में, जिनमें उत्तराखण्ड भी सम्मिलित है, उनकी भागेदारी को 50 प्रतिशत आरक्षित कर दिया गया। प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी जनपद में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागेदारी का आयु, जाति, शैक्षिक योग्यता के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

5. "डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं शिक्षा"—प्रोफेसर निधिबाला, प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.), सुरेश कुमार, शोध अध्येता शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, समाज सेवी, अर्थशास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ तथा महान राष्ट्र-भक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके चिन्तन और संघर्ष ने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। प्रस्तुत लेख डॉ. अम्बेडकर की स्वयं की शिक्षा तथा शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचारों के प्रस्तुतीकरण का एक प्रयास है।

6. "पुलिस का अपराधीकरण"—डॉ. निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, प्राचार्य/रीडर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी. (पी.जी.) कालेज, आजमगढ़ (उ.प्र.)

सांप्रतिक भारत में पुलिस की छवि धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली में उत्पीड़न, हिंसा, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति दिनोदिन समावेश करती जा रही है। प्रस्तुत लेख पुलिस के अपराधीकरण को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

7. "महिला सौन्दर्यीकरण के द्योतक "आभूषण" (कुमारुँ के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में)"—डॉ. सावित्री कैंडा जन्तवाल, उपाचार्य इतिहास विभाग, डी.एस.बी. परिसर, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कुमायूँ अंचल अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रख्यात है। इसलिए इस सुरम्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा धारण किये जाने वाले वस्त्रों एवं आभूषणों में भी कुमायूँ के सौन्दर्यशाली परिवेश तथा सांस्कृतिक परम्परा के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत लेख महिला सौन्दर्यीकरण के द्योतक-आभूषणों का कुमायूँ के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करने का एक प्रयास रहा है।

8. "वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं चुनौतियाँ"—डॉ. दक्षा जोशी, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (उत्तराखण्ड)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध ही नहीं अपितु अर्थव्यवस्थाएं भी अतिशय प्रभावित हो रही हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं चुनौतियों को प्रकाशित किया गया है।

9. "दूरदर्शन का बाल विकास पर प्रभाव"—डॉ. जकिया रफत, रीडर समाजशास्त्र विभाग, आर.बी.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, बिजनौर, श्रीमती भावना महरोत्रा, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, आर.बी.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, बिजनौर (उ.प्र.)

अध्ययन बताते हैं कि ज्यादा टी.वी. देखने से बच्चों की याद्दाश्त क्षमता व स्कूल प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल के बाद बचे समय में पुस्तकों, शारीरिक गतिविधियों, संगीत, प्रकृति के सानिध्य में या अन्य रचनात्मक कार्यों में खर्च होने वाला समय टी.वी. ले रहा है। वास्तव में टी.वी. देखना मनोरंजन का सबसे उत्तम व सुलभ साधन है परन्तु आज के समय में यह एक समस्या के रूप में सामने आया है। प्रस्तुत शोध पत्र बाल विकास में दूरदर्शन से उत्पन्न समस्याओं पर केन्द्रित किया गया है।

10. "नोवा आयरन एण्ड स्टील दगोरी, में सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन"—डॉ. के.के. सिंह, श्रम निरीक्षक, ए-19 बॉबजी नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.), अनिता पाठक, ट्रस्टी, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, प्रज्ञा पीठ, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के किसी उचित संगठन द्वारा सदस्यों को किन्हीं खतरों में प्रदान की जाती है। यह योजना दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था व मृत्यु के समय श्रमिकों या उनके परिवार को आर्थिक व चिकित्सकीय सहायता प्रदान करती है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत नोवा आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट

लिमिटेड दगोरी, बिलासपुर (छ.ग.) में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

**11. "महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप"—**कु. मन्जू भारती, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, ए.एन.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, कानपुर, श्रीमती नीलम चौहान, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, ए.एन.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, कानपुर, डॉ. अन्जू रानी, रीडर समाजशास्त्र विभाग, ए.एन.डी. गर्ल्स (पी.जी.) कालेज, कानपुर (उ.प्र.)

स्त्री-पुरुष समानता के संवैधानिक प्रावधान, महिलासंरक्षण एवं कल्याण की अनेकानेक योजनाओं तथा महिला अधिकारों हेतु सहायक विभिन्न सामाजिक विधानों के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा आज भी भारतीय समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। प्रस्तुत लेख महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा के स्वरूपों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

**12. "ब्रज लोक-साहित्य में नारी"—**डॉ. मिथलेश कुमारी दीक्षित, रीडर, समाजशास्त्र, के.के. (पी.जी.) कालेज, इटावा, कु. मोनिका, शोध अध्येत्री के.के. (पी.जी.) कालेज, इटावा (उ.प्र.)

ब्रज लोक-साहित्य के माध्यम से ब्रजक्षेत्र के समाज की संरचना में भारतीय नारी के नारीत्व का उत्कर्ष अधिक उभर कर सामने आया है। यहां पर नारी हृदय के भाव पक्ष ने अपनी अभिव्यक्ति-माता, कन्या, बहिन, पुत्री, पत्नी, सास, बहू, ननद, भाभी, सौतन, दासी, प्रेमिका के रूप में जिस प्रकार से की है उसका चित्रण भलीभाँति हुआ है। नारी के विविध रूपों का उन्हीं के रंगों में दर्शन होता है। प्रस्तुत लेख उसी चित्रण को संक्षेप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

**13. "हिन्दू एवं मुस्लिम महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"—** डॉ. रवीन्द्र बन्सल, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)

स्वतंत्रोपरांत महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किए गए अनेकानेक संवैधानिक प्रावधानों, शासकीय प्रयासों एवं गैर शासकीय प्रयत्नों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है किन्तु ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी सोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलायें अधिक पिछड़ी स्थिति में हैं। प्रस्तुत लेख ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन का एक प्रयास है।

**14. "मीणा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर"—** डा. मनोज कुमार तोमर, व्याख्याता- समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर, (राजस्थान)

जनजातीय समाज में स्वास्थ्य, रोग एवं चिकित्सा से संबंधित विश्वास, मूल्य एवं व्यवहार सम्पूर्ण संस्कृति के अभिन्न अंश हैं। अतः जनजातीय समाज के मूल्यों एवं संस्कृति से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी दोहरा मानदण्ड देखने को मिलता है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत राजस्थान की मीणा जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं रोग सम्बन्धी अभिवृत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

**15. "राजनीति में महिलाओं की भागीदारी - समाजशास्त्रीय संदर्भ"—**डॉ. ऊषा कुशवाह, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र जी. एल. एस. महाविद्यालय, बामौर, जिला - मुरैना (म.प्र.)

लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। स्वतंत्रोपरांत भारत में राजनीति में महिलाओं ने प्रवेश किया है तथा 73वें संविधान संशोधन ने इसे और भी गति प्रदान की है। अतः आवश्यक है कि सांप्रतिक भारतीय समाज में राजनीति में महिलाओं की सक्रियता एवं जागरूकता का आकलन किया जाय। प्रस्तुत लेख इसी दिशा में एक प्रयास है।

**16. "लैंगिक विषमता— एक सामाजिक समस्या"—**डॉ. वन्दना,वरिष्ठ प्रवक्ता समाजशास्त्र, वी.एस.एन.वी.(पी.जी.) कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.)

लैंगिक विषमता एक सार्वभौमिक समस्या है जो भारतीय समाज में अधिक गंभीर रूप धारण किये हुए है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की स्थिति तथा इसे दूर करने हेतु किये गये शासकीय प्रयासों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

**17. "वैश्वीकरण का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव"—** डॉ. उत्तरा यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महिला पी.जी. कालेज, लखनऊ (उ.प्र.)

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। परिवार और सामाजिक स्तर पर महिलायें अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत भारतीय महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों को प्रदर्शित किया गया है।

**18. "अध्यापक एवं राजनीति : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"—** डॉ अमिता सिंह,वरिष्ठ प्रवक्ता समाजशास्त्र, संत तुलसीदास (पी.जी.) कालेज, कादीपुर, सुल्तानपुर (उ.प्र.)

सदियों से घात-प्रतिघात, उत्थान-पतन में भी अविचल अखण्ड राष्ट्र के रूप में भारत माँ का साक्षात् दर्शन करने वाले गुरुजन सन्तों ने समय-समय पर मानस पुत्रों के माध्यम से समाज को संगठित किया, उनमें चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को, समर्थ रामदास ने शिवा को, स्वामी विरजानन्द ने दयानन्द को, श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द को या महर्षि अरविन्द ने जो समाज खड़ा किया उसमें गुरुओं की भूमिका अहम है। प्रस्तुत लेख में अध्यापक और राजनीति में संबन्धों के वर्तमान स्वरूप को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

**19. "भारतीय पुलिस प्रशासन — एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण"—**डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव,प्रवक्ता—समाजशास्त्र विभाग, महाविद्यालय बॉसडीह, बलिया (उ.प्र.)

भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1861 में लागू पुलिसतंत्रीय अधिनियम आज भी पुलिस व्यवस्था का आधार बना हुआ है। यही कारण है कि देश में कानून एवं व्यवस्था से सम्बंधित अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं तथा अपराधिक स्थिति से कारगर रूप से निपटने में पुलिस की क्षमता के प्रति जनमानस में संदेह उत्पन्न हो रहा है। प्रस्तुत लेख जन आकांक्षाओं, कानून एवं व्यवस्था के आलोक में पुलिस प्रशासन के मूल्यांकन का एक प्रयास रहा है।

**20. "जनपद टिहरी गढ़वाल में व्यापारिक / परम्परागत फसलों से रोजगार सृजन"—**डॉ. दिनेश सिंह नेगी, अंशकालिक प्रवक्ता अर्थशास्त्र विभाग हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

कृषि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र तथा गढ़वाल मण्डल में रोजगार का प्रमुख साधन है। कृषि व्यवसाय में श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने की क्षमता अनेक घटकों पर निर्भर करती है जिनमें व्यापारिक कृषि भी प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख के द्वारा टिहरी जनपद में व्यापारिक कृषि के विकास की वर्तमान स्थिति तथा भावी संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

**21. "प्राचीन मुद्राओं में संस्कृति का राष्ट्रीय एवं संश्लेषित स्वरूप"—**डॉ जिनेन्द्र जैन,संविदा व्याख्याता प्रा.भा.इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग डॉ हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि. सागर (म.प्र.)

अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज के साथ ही प्रकाशित तथ्यों को नए दृष्टिकोण एवं नवीन व्याख्या के द्वारा नई दिशा दी जाती है। अनुसंधान तभी सार्थकता प्राप्त करता है जब नई दिशा समसामयिक महत्व को

प्रतिपादित करे। पुरातत्विक अनुसंधान से जो नवीन सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनकी व्याख्या ज्ञान व विचारों के आयाम को व्यापक बनाती है। प्रस्तुत लेख इसी दिशा में एक प्रयास रहा है।

**21. "गढ़वाल हिमालय में वृद्ध एकाकी महिला का जीवन"—**डॉ. अर्चना बहुगुणा, अंशकालिक प्रवक्ता मानवशास्त्र विभाग, हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सांप्रत समाज में वृद्ध-संस्कृति एवं उसकी समस्याएं अपने में एक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय विषय बन चुका है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत गढ़वाल हिमालय की वृद्ध एकाकी महिलाओं की स्थिति एवं उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है।

**22. "बाल श्रम-समस्या तथा उन्मूलन"—**श्रीमती कीर्ति, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

बालश्रम आज विश्व की गंभीरतम सामाजिक बुराइयों में से एक है। यह नागरिक विकास की परिकल्पना में सबसे बड़ी बाधा है। प्रस्तुत लेख इस चिंताजनक समस्या की स्थिति और उन्मूलन के प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

**23. "पं. श्रीराम शर्मा का असहयोग आन्दोलन में योगदान"—**शीला कुमारी, शोधअध्येत्री, इतिहास विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

महात्मा गांधी ने नवम्बर 1919, में दिल्ली में असहयोग आन्दोलन की बात कही थी। 1 अगस्त, 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 4 दिसम्बर, 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सरकार को सहायता न देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तुत लेख इस असहयोग आन्दोलन में पं. श्रीराम शर्मा के योगदान को प्रकाशित करने का एक प्रयास रहा है।

**24. "भिवानी नगर में असहयोग आन्दोलन (1920-1922)"—**इन्दिरावती, शोध अध्येत्री, इतिहास विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

महात्मा गांधी ने नवम्बर 1919, में दिल्ली में असहयोग आन्दोलन की बात कही थी। 1 अगस्त, 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 4 दिसम्बर, 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सरकार को सहायता न देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तुत लेख में इस देशव्यापी असहयोग आन्दोलन में भिवानी नगर की भूमिका को उजागर किया गया

**25. "औपनिवेशिक भारत में नागरिक सेवा का उदय और विकास"—**डॉ. राजबीर सिंह, वरिष्ठ प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय, झज्जर (हरियाणा)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रारम्भ में असंगठित नौकरशाही से ही काम चलाया किन्तु प्रशासन का व्यापक विस्तार होने से शक्तिशाली नौकरशाही की आवश्यकता अनुभव हुई और एक संगठित नागरिक सेवा व्यवस्था को विकसित किया। प्रस्तुत लेख औपनिवेशिक भारत में नागरिक सेवा के उदय और विकास का ऐतिहासिक चित्रण प्रस्तुत करता है।

**26. "औपनिवेशिक भारत में कानूनी प्रक्रिया का विकास"—**डॉ. दलजीत सिंह, ग्राम व डाकघर राजथल, जिला हिसार (हरियाणा), रोशन लाल, शोध अध्येत्री, इतिहास विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

1813 तक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी अधिकतर परम्परागत भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप कार्य करती रही। किन्तु जब कम्पनी ने भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किये तो भारत के

समस्त संसाधनों पर भी उनसे नियंत्रण करना आवश्यक समझा। अतः उसने अपने हितों एवं उद्देश्यों के अनुरूप कानूनी प्रक्रिया का विकास किया। प्रस्तुत लेख आपैनिवेशिक भारत में कानूनी प्रक्रिया के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास कहा जा सकता है।

**27. "कायस्थों का उद्भव एवं विकास – मिथ एवं यथार्थ"**—रत्ना श्रीवास्तव, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, सी. एस. जे. एम. विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

प्रस्तुत लेख के अंतर्गत धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर कायस्थ जाति के उद्भव एवं विकास का वास्तविक एवं यथार्थ विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

**28. "महिला कल्याणकारी कार्यक्रम एवं महिला विकास"**—हर्ष कुमार श्रीवास्तव, शोध अध्येता, श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी.जी. कालेज, परमानन्दपुर, वाराणसी (उ.प्र.)।

स्वतंत्रोपरांत भारत में शिक्षा प्रसार तथा उनकी सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने हेतु शासन तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विविध प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत, महिला कल्याण की कतिपय योजनाओं के संदर्भ में महिला विकास पर प्रकाश डाला गया है।

**29. पुस्तक समीक्षा**—पुस्तक का नाम — 'मलिन बस्ती की महिलायें अपराध और पुलिस' लेखिका— डा. आभा सक्सेना, रीडर समाजशास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी कालेज, वाराणसी, समीक्षक— प्रोफेसर जे.पी. पचौरी, अध्यक्ष— समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे.न.ब. केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)